and notified the Employees' Pension Scheme, 1995 which would benefit over 150 million workers and their families. The Scheme has already come into force with effect from #6.11.95.

It would not be correct to hold that the Pension Scheme is anti-labour. The Scheme was evolved by the Central Board of Trustees on which, besides others, Central Trade Union Organisations are also represented. Before and after the Scheme was recommended by the Central Board of Trustees, a wider consultation with the Central Trade Union Organisations has taken place. All The Central Trade-Union Organisations except CITU and UTUC(LS) have generally supported the Pension Scheme with some suggestions for making improvements. These suggestions would be examined with a view to finding out if it would be possible to make any improvement in the Scheme without affecting its economic sustainability. Besides other suggestions CITU has suggested that pension should be given as a third benefit and that membership of the Scheme should be made optional. As pension and Central Provident Fund are considered mutually exclusive, it is not possible to give pension as a third benefit. It would also not be possible to make the membership of the Scheme optional as in the event of it being made optional, acturial calculations will just not be feasible because there would be no definiteness about contribution to the Scheme which is necessary in every contributory Scheme. The Scheme, however, provides for exemption of establishments if they have their own comparable or superior Pension Schemes.

The Scheme is meant for providing security to the workers and their families during the service of the workers and even after their retirement/death. As such there is no provision in the Scheme which could adversely affect the working class.

जनजातीय लोगों को सामान्य दरों पर खाद्यान्न जारी किया जाना

1361. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जनजातिय क्षेत्रों में स्थापित खाद्यान्न डिपो से सामान्य पर खाद्यान्न जारी करने का विचार रखती है,

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो जनजातिय लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जनजातीय क्षेत्र उपयोजना स्कीम के अंतर्गत सामान्य दरों पर खाद्यान्न की आपूर्ति न किए जाने के क्या कारण है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग)(श्री विनोद शर्मा): (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों, जिनमें समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं, आदिवासी बहुल राज्यों तथा करीब-एंग्लोंग तथा असम के उत्तरी कछार में पहाड़ी जिले के तहत आने वाले सभी ब्लाक शामिल है, में विवरण के लिए अभिप्रेत खाद्यान्न विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर जारी किए जाते हैं, जो सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों हेतु केन्द्रीय निर्गम मूल्यों की तुलना में 50 रू. प्रति क्विंटल कम है। इन आदिवासी क्षेत्रों में वितरण के लिए अभिप्रेत वाले खाद्यान्नों पर इस विशेष राजसहायता को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम मे ठेकेदारी प्रथा

1362. **श्रीमती सुषमा स्वराज** :

श्री राम जेठमलानी:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा ठेकेदारी प्रथा के तहत कार्य किया जाता है,

(ख) यदि हां, तो निगम में किन-किन कार्यो के लिए ठेकेदारी प्रथा को अपनाया गया है,

(ग) क्या इस ठेकेदारी प्रथा के तहत कार्य आवंटन

^ हेतु कोई स्थायी व्यवस्था की गई है,

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ड.) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-954 के दौरान निगम द्वारा ठेकेदारी प्रथा के तहत किए गए समस्त कार्यों के लिए खर्च की गई धनराशियों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्नों के हैंडलिंग और परिवहन का अधिकाशं कार्य ठेका प्रणाली के अधीन किया जाता है।

(ग) और (घ) हैंडलिंग और परिवहन ठेकेदारों की नियुक्तियां खुली निविदा इंक्वायरी के माध्यम से की जाती है जिसके लिए प्रमुख राष्ट्रीय/स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं। ठेके देते समय अन्य बातों के साथ-साथ निविदाकारों का पिछला अनुभव, कारोबार संबधी सामर्थ्य वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखा जाता है।

(ड.) ठेके पर किए गए कार्य पर हुआ वर्षवार व्यय निम्नानुसार है :-

वर्ष	रूपए/करोड़
1992-93	210.61
1993-94	257.84
1994-95	272.61

Export of Rice

1363. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) what is the total quantity of rice which was exported out of the total rice in the godowns and the rate of export;

(b) whether it is a fact that export rate was less than the purchase rate;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) what is the broken percentage of such rate?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) In view of the comfortable stock position of foodgrains in the central pool, the Food Corporation of India has been authorised to export/ sell for the purpose of export a quantity of 2.00 million tonnes of fine and superfine rice during 1995-96 at the rates fixed by the Government from time to time. The Food Corporation of India has not exported any quantity of rice directly. However, it has sold, upto November, 1995, about 15 lakh tonnes of fine and superfine rice to private exporters and Public Sector Undertakings (STC MMTC & PEC) for the purpose of export. The prevailing export sale rates are given in the enclosed statement. *(See* below)

(b) and (c) No Sir, the price for the sale of rice for the purpose of export is above levy price fixed by the Government of India but less than the Economic Cost of Food Corporation of India.

(d) Broken percentage

Variety		Tolerance Limit	Rejection Limit
Fine	Raw	20%	25%
	Boiled	17%	22%
Superfine	Raw	18%	23%
	Boiled	13%	18%

Statement

Price of Rice for the purpose of Exports w.e.f. 28.11.95

S.No.	Name of the State/Port town	(RATE: RUPEES PER METRIC TONNES) Sale price of fine/ superfine rice for the purpose of export under the open market sates scheme.	
		Fine (Raw/ Boiled)	Superfine (Raw/ Boiled)
1	2	3	4
1.	Punjab	7110	7420
2.	Haryana	7050	7370
3.	U.P.	7050	7210